(च) तथा (छ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सैनिक फार्म में 1990 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पी.सं० 86-ए के बारे में सुरजीत सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम के एक मामले में स्थगन आदेश दिया हुआ है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है ।

Flood prone areas in the State of Bihar

637. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) which are the flood prone areas in the State of Bihar,

(b) out of these areas, which areas suffered from floods during the last three years;

(c) the estimates of damage done due to floods submitted by Bihar Government luring the last three years;

(d) the amount of aid provided by the Central Government against those estimates during the last three years. and

(e) the reasons of the differences, if any, between the estimates submitted by the Bihar Government and the Central assistance provided for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Rashtriya Barh Ayog has assessed an area of 42.6 lakh hectare as flood prone in the State of Bihar. On an average an area of about 14.45 lakh hectare gets affected annually. During the last three years 14 districts were mainly affected due to floods viz., Darbhanga, Gopalganj, Khagaria, Bhagalpur, Madhubani, Muzaffarpur, Madhepura, Patna, Saharsha, Supaul, Sitamarhi, Samastipur, West Chaparan and Katihar.

(c) to (e) Government of Bihar has reported damage to crops, houses and public utilities to the extent of Rs 20.14 crores, Rs. 22.14 lakhs and Rs. 306.41 crores during 1991-92, 1992-93 and 1993-94 respectively. Under the existing scheme of financing relief expenditure, the State Government undertakes relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities including floods using the corpus of the calamity Relief Fund (CRF). Bihar has an annual CRF of Rs. 35.00 crores consisting of Central share of Rs. 26.25 crore and State share of Rs. 8.75 crore. The Central share of CRF has been released to the State Government during the last 3 years for undertaking relief and rehabiltation measures in wake of natural calamities.

सरदार सरोवर परियोजना पर पुनर्विचार करने से संबंधित प्रतिवेदन की जांच

638. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सरदार सरोवर परियोजना पर पुनर्विचार करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन की जांच करने के लिए सरकार को निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थूगन) (क) से (घ) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार की अनुक्रियायें सुनवाई की अगली तारीख अर्थात् 13-12-94 को न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए । तथापि, इस रिपोर्ट की गोपनीयता को बनाए रखा जायेगा ।

उड़ीसा में पोलेरु सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाना

639. **श्री भगवान माझी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिग्रहण समस्या और अन्य अवरोधों को, जिनसे उड़ीसा में पोलेरु